



दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHIN/2018/76480

Postal Registration No-055/Raigarh DN CG

रायगढ़, रविवार 08 दिसंबर 2024

पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए

वर्ष-07, अंक- 70

महत्वपूर्ण एवं खास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी, मुंबई पुलिस को आया मैसेज

मुंबई (आरएनएस) मुंबई पुलिस को एक मैसेज मिला है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दी गई है। मुंबई पुलिस को ये मैसेज व्हाट्सएप पर भेजा गया है। मैसेज मिलते ही पुलिस अलर्ट हो गई है और जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ये मैसेज राजस्थान से भेजा गया था। मैसेज भेजने वाले की तलाश में एक टीम को अजमेर भेजा गया है। एक अधिकारी ने बताया कि मुंबई ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन आज (7 दिसंबर) की सुबह ये मैसेज भेजा गया है। इसमें आईएसआई के 2 एजेंटों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश के बारे में बताया गया है। मैसेज के मुताबिक, दोनों एजेंट प्रधानमंत्री मोदी को बम से उड़ाने की साजिश रच रहे हैं। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। इससे पहले 27 नवंबर को मुंबई पुलिस को फोन कर प्रधानमंत्री मोदी को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई थी। मामले में पुलिस ने एक महिला को हिरासत में भी लिया था, जो मानसिक रूप से अस्थिर थी। 17 नवंबर मुंबई पुलिस को लॉरिस बिश्रोई के नाम से कई मैसेज आए थे, जिसमें कहा गया था कि अगर सलमान खान ने 5 करोड़ रुपये नहीं दिए तो उनकी हत्या कर दी जाएगी।

अजित पवार को बेनामी संपत्ति मामले में क्लीन चिट, लौटाई गई 1,000 करोड़ की संपत्ति

मुंबई (आरएनएस) महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार को आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति मामले में क्लीन चिट दे दी है। एक दिन पहले ही उन्हें दिल्ली में बेनामी संपत्ति लेने-देने रोकथाम अपीलीय न्यायाधिकरण से राहत मिली थी। आयकर विभाग ने 2021 में उनसे जुड़ी संपत्तियों को जब्त किया था, लेकिन न्यायाधिकरण को पवार परिवार से जुड़े बेनामी लेने-देने का कोई सबूत नहीं मिला। इसमें कहा गया है, अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत सामग्री किसी भी बेनामी लेने-देने को नहीं दर्शाती है। पवार के खिलाफ यह मामला 7 अक्टूबर, 2021 का है, जब आयकर विभाग ने कई कंपनियों पर छापेमारी की थी। छापेमारी में जब्त किए गए दस्तावेजों में कथित तौर पर कुछ संपत्तियों का संबंध पवार और उनके परिवार से था। हालांकि, न्यायाधिकरण ने सबूतों के अभाव में आरोपों को खारिज कर दिया। द्वारा जब्त की गई संपत्ति की कीमत 1,000 करोड़ रुपये से अधिक थी। इनमें एक चीनी मिल, दिल्ली का एक फ्लैट और गोवा का एक रिसॉर्ट शामिल है। अपना फैसला सुनाते हुए न्यायाधिकरण ने कहा कि उसे पवार के खिलाफ बेनामी संपत्ति के मालिक होने के कोई ठोस सबूत नहीं मिले और संबंधित संपत्तियों के लिए सभी वित्तीय लेन-देन वैध चैनलों के माध्यम से किए गए थे। न्यायाधिकरण ने कहा, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अज्ञित पवार या उनके परिवार ने बेनामी संपत्ति हासिल करने के लिए धन हस्तांतरित किया। पवार के अधिवक्ता प्रशांत पाटिल ने कहा कि पवार परिवार पर आरोप निराधार हैं।

जम्मू-कश्मीर में शीत लहर के बीच बारिश-बर्फबारी का अलर्ट

श्रीनगर (आरएनएस) तापमान में गिरावट के साथ कश्मीर घाटी में शीत लहर जारी है। श्रीनगर से लेकर लेह तक तापमान शून्य से नीचे पहुंच गया। लेह में रात का तापमान -1.9 डिग्री रिकार्ड किया गया और काशीगल का हाल कश्मीर से भी बुरा है। यहां का तापमान यहां का तापमान माइनस 10 डिग्री तक नीचे चला गया है। कश्मीर के हर हिस्से में तेजी से गिर रहे तापमान के कारण ठंड की शिहत बढ़ने लगी है जिसे देखते हुए प्रशासन ने फेस वाइस स्कूलों में विट्ट वेकेशन की घोषणा की है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल लोगों को इस ठंडरती की ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है बल्कि आने वाली रातें और ज्यादा सर्द हो जाएगी। जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को दक्षिण कश्मीर के शोपियां में न्यूनतम तापमान -6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुलमर्ग और पल्लगाम के स्की रिसॉर्ट्स में न्यूनतम तापमान क्रमशः 4.3 डिग्री सेल्सियस और 6.5 डिग्री सेल्सियस था। उत्तरी कश्मीर जिले के कुवाड़ा में न्यूनतम तापमान शून्य से 3.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि कश्मीर के प्रवेश द्वार शहर काजीगुंड में न्यूनतम तापमान शून्य से 4.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, 8-9 दिसंबर को आमतौर पर जम्मू संभाग के मैदानी और पहाड़ी इलाकों के कुछ इलाकों में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश भी हो सकती है।

देशभर में खुलेंगे नए केंद्रीय और नवोदय विद्यालय, मोदी कैबिनेट से मिली मंजूरी

नई दिल्ली। आरएनएस

देशभर में नए केंद्रीय और नवोदय विद्यालय खोलने का रास्ता साफ हो गया है। मोदी कैबिनेट ने कुल 85 केंद्रीय विद्यालय और 28 नवोदय विद्यालयों को खोलने की मंजूरी दे दी है। इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अंतिम छोर पर बैठे लोगों के बच्चों तक भी पहुंच सकेगी।

पीएम मोदी ने अपने एक्स अकाउंट से लिखा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप स्कूली शिक्षा समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसी कड़ी में हमारी सरकार ने देशभर में 28 नए नवोदय विद्यालयों को मंजूरी दी है। इससे आवासीय और गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा का बड़े दायरे में विस्तार होगा।

पीएम मोदी ने एक अन्य ट्वीट में कहा, स्कूली शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा सुलभ बनाने के लिए हमारी सरकार ने एक और



बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत देशभर में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। इस कदम से जहां बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को लाभ होगा, वहीं रोजगार के भी बहुत सारे नए अवसर बनेंगे।

जानकारी के मुताबिक, केंद्र की मोदी सरकार आगे 8 सालों में इन विद्यालयों को खोलने के लिए आठ हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी। ये सभी स्कूल पीएम-श्री स्कूलों के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में इन स्कूलों को खोलने पर अहम फैसला लिया गया।

मोदी कैबिनेट में लिए गए फैसलों की

जानकारी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। उन्होंने कहा कि, देश के 19 राज्यों में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। इनमें एक केंद्रीय विद्यालय दिल्ली के खजुरी खास में भी खोला जाएगा। इन 85 नए केंद्रीय विद्यालयों के खोलने से 82 हजार से ज्यादा छात्रों को पढ़ाई लिखाई का मौका मिलेगा। कैबिनेट ने कर्नाटक के शिमोगा जिले में पहले से चल रहे एक केंद्रीय विद्यालय को अपग्रेड करने का भी फैसला लिया है।

वहीं जिन नए 28 नवोदय विद्यालयों को खोला जाएगा उनमें 15 हजार से ज्यादा छात्रों को प्रवेश मिलेगा। इसके साथ ही 1300 से अधिक नए लोगों को शिक्षक सहित दूसरे पदों पर नौकरी का भी मौका मिलेगा। केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए मोदी सरकार करीब 5872 करोड़ रुपये खर्च करेगी, जबकि नए नवोदय विद्यालयों को खोलने का खर्च करीब 2360 करोड़ रुपये आएगा। बता दें कि वर्तमान में देशभर में 1,256 केंद्रीय विद्यालय हैं। इनमें से तीन विदेशों में हैं। जिनमें मॉस्को,

काठमांडू और तेहरान एक-एक केंद्रीय विद्यालय हैं।

केंद्र सरकार जो 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने जा रही है उनमें 13 विद्यालय जम्मू-कश्मीर, 11 मध्य प्रदेश, 09 राजस्थान, 08 ओडिशा, 08 आंध्र प्रदेश, 05 उत्तर प्रदेश, 04 उत्तराखंड, 04 छत्तीसगढ़, 04 हिमाचल प्रदेश, 03 कर्नाटक और एक स्कूल को अपग्रेड किया जाएगा। इनके अलावा तीन स्कूल गुजरात, तीन महाराष्ट्र, दो झारखंड, दो तमिलनाडु, दो त्रिपुरा, एक दिल्ली, एक अरुणाचल प्रदेश, 1-1 स्कूल असम और केरल में खोला जाएगा।

इसमें अरुणाचल प्रदेश में आठ, तेलंगाना में सात, असम में छह, मणिपुर में तीन, पश्चिम बंगाल में दो, कर्नाटक और महाराष्ट्र में एक-एक नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे, वहीं उत्तर प्रदेश में जो 5 केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे वे प्रयागपुर-जौनपुर, महाराजगंज, बिजनौर, चांदपुर-अयोध्या, कन्नौज जिलों में खुलेंगे।

बिहार के मशहूर टीचर खान सर की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में हुए भर्ती

पुलिस ने गिरफ्तारी की अफवाहों का किया खंडन

पटना। आरएनएस

बिहार के मशहूर कोचिंग टीचर खान सर की तबीयत अचानक खराब हो गई है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि उन्हें डिहाइड्रेशन और बुखार हुआ है। फिलहाल, उनकी स्थिति स्थिर है और वह डॉक्टरों की निगरानी में हैं। दरअसल, खान सर पटना के गर्दनीबाग में बीपीएससी उम्मीदवारों के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। इस दौरान यह चर्चा होने लगी थी कि उन्हें हिरासत में लिया गया है, लेकिन पटना पुलिस ने स्पष्ट किया कि खान सर को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

पुलिस ने उन्हें उनके वाहन के पास छोड़



दिया था, हालांकि, अफवाहों के बीच खान सर की तबीयत और बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। यह घटना तब हुई जब खान सर 6 दिसंबर को बीपीएससी उम्मीदवारों के साथ परीक्षा के नियमों में बदलाव के खिलाफ विरोध कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था। विरोध के अगले दिन, शनिवार को उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई जिसमें आरोप लगाया गया कि उनके ट्विटर हैंडल से फर्जी पोस्ट किए गए हैं, जो छात्रों को गुमराह कर रहे थे।

वर्तमान में खान सर की हालत स्थिर है और उन्हें डिहाइड्रेशन और बुखार के कारण इलाज मिल रहा है। उनके स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए उनके समर्थकों और छात्रों ने उनके जल्दी ठीक होने की कामना की है।

देश के हवाई अड्डों की निगरानी बढ़ाएगा सीआईएसएफ, बनाई स्पेशल यूनिट

नई दिल्ली। आरएनएस

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने देश के सभी 68 नागरिक हवाई अड्डों पर तैनात विमानन सुरक्षा समूह (एएसजी) के लिए एक आंतरिक गुणवत्ता नियंत्रण इकाई (आईक्यूसीयू) बनाई है। इस इकाई का मकसद विदेश स्तरीय सुरक्षा प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है।

सीआईएसएफ के अनुसार, आईक्यूसीयू विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र (एएससीसी) के अंतर्गत कार्य करेगा। एएससीसी को भी हाल ही में शुरू किया गया है। इसका उद्घाटन 22 जुलाई, 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने किया था।

एएससीसी मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए आईक्यूसीयू के साथ



मिलकर काम करेगा और घटना प्रबंधन केंद्र, विमानन अनुसंधान और डेटा केंद्र, केंद्रीकृत संचार नियंत्रण केंद्र के साथ भारतीय हवाई अड्डों की समग्र सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। यह प्रणाली क्षेत्रीय संपर्क योजना (उड़ान) के तहत हवाई अड्डों को भी कवर करेगी।

आईक्यूसीयू का नेतृत्व वरिष्ठ सीआईएसएफ अधिकारी करेंगे और इसमें प्रमाणित विमानन सुरक्षा (एवीएससी) प्रशिक्षक, राष्ट्रीय

लेखा परीक्षक और इसके कर्मचारी शामिल होंगे। वे मानकीकृत प्रशिक्षण और मूल्यांकन विधियों, फील्ड ट्रायल और अंतरराष्ट्रीय नई तकनीकों को अपना देने के माध्यम से हवाई अड्डों पर सुरक्षा प्रक्रियाओं में एकरूपता सुनिश्चित करेंगे।

आईक्यूसीयू सुरक्षा कार्यों का मूल्यांकन करने और सुधारात्मक उपायों को लागू करने के लिए विभिन्न दिशानिर्देशों के आधार पर आंतरिक निरीक्षण और ऑडिट करेगा। जिससे हवाई अड्डों की खामियों को दूर कर उसे सुधारने में मदद मिलेगी। साथ ही अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन के मानकों को ध्यान में रख सभी जगह से फीडबैक ले उसका विश्लेषण किया जाएगा।

इस सिस्टम को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत आने वाले एयरपोर्ट पर भी समान रूप से लागू किया जाएगा।

इससे पहले, अर्धसैनिक बल के एक प्रवक्ता ने शनिवार को जानकारी दी थी कि आंतरिक गुणवत्ता नियंत्रण इकाई (आईक्यूसीयू) हवाई अड्डों पर उच्चतम स्तर की प्रक्रियाओं और तकनीकों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इन हवाई अड्डों पर हर दिन लाखों घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्री यात्रा के लिए आते हैं।

उन्होंने बताया कि यह पहल सीआईएसएफ द्वारा राष्ट्रीय नागरिक विमानन सुरक्षा गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रम 2024 के तहत की जा रही है। यह कार्यक्रम नागरिक विमानन सुरक्षा ब्यूरो और विमान (सुरक्षा) नियम, 2023 के तहत जारी किया गया था।

बीच सड़क पर अंधाधुंध फायरिंग, 12 घंटे के अंदर 3 मर्डर : केंद्रीय मंत्री से भी मांगी गई लाखों की रंगदारी

नई दिल्ली। आरएनएस

देश की राजधानी दिल्ली अब क्राइम की कैपिटल भी बन चुकी है। आमजन से लेकर खास लोग दिल्ली में अपराधिक मामलों के शिकार हो रहे हैं। पिछले 12 घंटे के अंदर दिल्ली में कई बड़ी अपराधिक घटनाएं सामने आईं हैं। पहली घटना केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जाने की है।

धमकी देने वाले शख्स ने मंत्री के फोन पर मैसेज भेजा है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने इस मामले की शिकायत दिल्ली पुलिस और झारखंड के डीजीपी से की है। संजय सेठ झारखंड से सांसद हैं। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है।



दिल्ली के शहादरा में शनिवार सुबह बंदमशाओं ने बीच सड़क पर गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी। मृतक की पहचान सुनील जैन के रूप में हुई है। वह बर्तन व्यापारी था। बमाशाओं ने 6-7 राउंड फायर कर बर्तन व्यापारी की हत्या कर दी। हत्या किस वजह से की गई है अभी इसको लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।

दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में कॉमन टॉयलेट की सफाई को लेकर पड़ोसियों के बीच झगड़े के बाद हत्या की वारदात सामने आई है। शुक्रवार रात 12:07 बजे गोविंदपुरी थाने में झगड़े की पीसीआर कॉल पुलिस को मिली। जिसमें दो पड़ोसियों ने एक दूसरे को पीटा था। पुलिस के अनुसार, सुधीर के सीने, चेहरे और सिर पर चाकू से वार किए गए। मारपीट के बाद सुधीर, उसके भाई प्रेम और उनके दोस्त सागर को एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया।

गई 22 वर्षीय प्रेम गंभीर रूप से घायल होने के चलते बयान के लिए अयोग्य है। 20 वर्षीय सागर को अस्पताल से छुड़ी दे दी गई है। पुलिस ने आरोपी भीकम सिंह, उसकी पत्नी मीना और उनके तीन बेटों संजय, राहुल और एक नाबालिग बेटे को हिरासत में लिया है। भीकम गोविंदपुरी में बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पर काम करता है।

यदाद्री भुवनगिरी में कार तालाब में गिरी, पांच लोगों की मौत

भुवनगिरी। आरएनएस

यदाद्री भुवनगिरी जिले में शनिवार को एक कार अनियंत्रित होकर तालाब में गिर गई। इस हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति सुरक्षित बच गया है।



मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह हादसा जिले के भूदान पांचमपल्ली में जलापुर के पास शनिवार सुबह 4:30 बजे हुआ। दुर्घटना के समय पोचमपल्ली जा रहे थे। हालांकि, उनमें से एक मणिकांठा कार की खिड़कियां तोड़कर सुरक्षित बच गया। सभी रात को अपने घरों से निकले थे और वे हैदराबाद से भूदान पोचमपल्ली जा रहे थे। ऐसा संदेह है कि घटना के समय वे शराब के नशे में थे।

हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस कर्मियों ने स्थानीय ग्रामीणों की सहायता से डूबे वाहन से शवों को निकालने में सफलता पाई। शवों

को पोस्टमार्टम के लिए भुवनगिरी सरकारी अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस पोस्टमार्टम के बाद शव परिवर्जनों को सौंप देगी। एकमात्र जिंदा बचे मणिकांठा को फिलहाल निगरानी में रखा गया है। पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान हैदराबाद के एलबी नगर निवासी वॉमिस (23), दिनेश (21), हर्षा (21), बालू (19) और विनय (21) के रूप में हुई है। वहीं मणिकांठा (21) हादसे में सुरक्षित बच गया है। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि दुर्घटना के समय समूह शराब के नशे में था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है।

टीडीएफ योजना के तहत 334.02 करोड़ लागत वाली 79 परियोजनाओं को मिली मंजूरी

नई दिल्ली। आरएनएस

रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए प्रौद्योगिकी विकास निधि (टीडीएफ) योजना के तहत अब तक 79 परियोजनाएं मंजूरी की गई हैं, जिनकी लागत 334.02 करोड़ रुपये है।

इसके अलावा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने देश भर में 15 उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र (डीआईए-सीओ) स्थापित किए हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में यह जानकारी दी।

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा मेक इन इंडिया पहल के तहत प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना रक्षा मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। केंद्र



सरकार ने उद्योगों, विशेष रूप से एमएसएमई और स्टार्टअप को विभिन्न रक्षा प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए इस योजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उद्योगों को अनुदान सहायता के रूप में प्रति परियोजना 50 करोड़ रुपये तक का प्रदान किया जाएगा। डीआरडीओ ने रक्षा और सुरक्षा के लिए नई टेक्नोलॉजी के विकास में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए आईआईएससी बैंगलोर, विभिन्न आईआईटी और

केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों जैसे संस्थानों में डीआईए-सीओई की स्थापना की है। ये उत्कृष्टता केंद्र शोधकर्ताओं और विद्वानों को आकर्षित करने के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं, अनुसंधान सुविधाओं और बुनियादी ढांचे से सुसज्जित हैं।

इन केंद्रों के माध्यम से, डीआरडीओ का लक्ष्य उत्पाद विकास को आगे बढ़ाने के लिए स्टार्टअप और उद्योगों के साथ प्रभावी सहयोग स्थापित करना है। सरकार ने रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्रों में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के विकास को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस प्रेमवर्क को लॉन्च किया है।

यह आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई, स्टार्टअप,

व्यक्तिगत इनोवेटर्स, आरएंडडी संस्थानों और शिक्षाविदों सहित उद्योगों को शामिल करता है। मई 2021 में, सरकार ने पांच साल (2021-22 से 2025-26) के लिए 498.80 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन के साथ इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस को बढ़ाने के लिए एक योजना शुरू की।

इस योजना का उद्देश्य रक्षा नवाचार संगठन (डीआईओ) ढांचे के तहत लगभग 300 स्टार्टअप, एमएसएमई और व्यक्तिगत इनोवेटर्स के साथ-साथ 20 पाठन इनक्यूबेटर्स को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अब तक डीआरडीओ की अनुदान सहायता योजना के तहत लगभग 930 करोड़ रुपये की 264 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

पूजा स्थल अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

नई दिल्ली। आरएनएस

सुप्रीम कोर्ट 12 दिसंबर को पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के कुछ प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की विशेष पीठ दोपहर 3:30 बजे मामले की सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह कानून मनमाना और अनुचित है और धर्म का पालन करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है।

याचिकाओं में कहा गया है कि यह अधिनियम हिंदुओं, जैन, बौद्ध और सिखों से उनके पूजा स्थलों और तीर्थस्थलों को बहाल करने के अधिकारों को छीनता है, जिन्हें पहले आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया था या याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि यह

अधिनियम मनमाना है, धर्मनिरपेक्षता और कानून के शासन के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है और अदालत में जाने और न्यायिक उपाय मांगने के अधिकार को भी छीन लेता है। मुख्य याचिका धार्मिक गुरु और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने 2020 में दायर की थी। इस पर कोर्ट ने मार्च, 2021 में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। इसके बाद काशी राजघराने की बेटी, महाराजा कुमार कृष्ण प्रिय, भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी, पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय, धार्मिक नेता स्वामी जीतेंद्रानंद सरस्वती और मथुरा के देवकीनंदन टाकूर समेत कुछ और लोगों ने अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का खर्च किया है।

जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने भी हिंदू याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर याचिकाओं को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है।

पुलिस ने बताया कि इस मामले में हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। पश्चिमी दिल्ली में बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी। शुक्रवार को पुलिस को इस हत्या की जानकारी मिली। दरअसल न्याय के एक शख्स फोन कर पुलिस को बताया कि उसकी मां की हत्या हो गई है। उसकी मां की ज्वेलरी गायब है।

जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को मौके से कोई भी ऐसा सुराग हाथ नहीं लगा, जिससे ये साबित हो सके कि चोरी हुई है। इसके बाद पुलिस को सावन नाम की जानकारी मिली। दरअसल सावन का एक शख्स फोन कर पुलिस को बताया कि उसकी मां की हत्या हो गई है। उसकी मां की ज्वेलरी गायब है।

पुलिस ने बताया कि आरोपी और पीड़ित दोनों गोविंदपुरी की गली नंबर 6, 482 में बिल्डिंग की पहली मंजिल पर किराएदार हैं। उनका कॉमन टॉयलेट था। झगड़ा तब शुरू हुआ जब एक लोगों द्वारा कॉमन टॉयलेट का इस्तेमाल किया गया और सफाई को लेकर झगड़ा होने लगा। पुलिस ने इस मामले में एक ही परिवार के 5 सदस्यों को हिरासत में लिया है।